Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP, Ludhiana, Shimla, Bihar, Jammu, Jaipur Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9815619715
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper

Published from SAS Nagar (Mohali)

Azad वाणी

NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No. PBBIL/26/A0779

पंजाब बनेगा खेल महाशक्ति, खिलाड़ियों पर 32.05 करोड़ रुपये की पुरस्कार वर्षा: भगवंत मान

चंडीगढ़, 24 मई 2026: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के खेल इतिहास की सबसे बड़ी खेल प्रोत्साहन पहलों में से एक की घोषणा करते हुए 87 महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार विजेताओं और 1,070 पदक विजेता खिलाड़ियों को कुल 32.05 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अब केवल जीत के बाद सम्मान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं से पहले ही आर्थिक सहायता देकर उनकी तैयारी को मजबूत करेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए खेल बजट को बढ़ाकर रिकॉर्ड 1,763 करोड़ रुपये किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 1,300 करोड़ रुपये की लागत से 3,148 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 6,000 गांवों में जिम उपकरण लगाए जा रहे हैं और 17,000 खेल किट वितरित की जा रही हैं।

भगवंत मान ने घोषणा की कि पंजाब पहली बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा और बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला पंजाब दिवस पर आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि पहले खेल संघ राजनीतिक लोगों के नियंत्रण में थे, लेकिन अब खिलाड़ियों को योग्यता के आधार पर अवसर दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पहली बार 220 खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए 8.61 करोड़ रुपये की सीधी सहायता दी है। खेल पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और आधुनिक खेल उपकरणों के लिए 15 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं। शूटिंग, फेंसिंग, कयाकिंग और तीरंदाजी जैसे खेलों के लिए विशेष सहायता भी दी जा रही है।

कार्यक्रम के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और खिलाड़ी अमनजोत कौर को 1.50-1.50 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के खिलाड़ियों ने देश और राज्य का नाम दुनिया भर में रोशन किया है और सरकार उनके सम्मान व भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने "आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन" कैडर बनाकर खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। 500 पद सृजित किए गए हैं, जबकि खेल विज्ञान के लिए अलग स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर स्थापित करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेक्टर-42, चंडीगढ़ में 43.66 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले युवा भवन का शिलान्यास भी किया।

सीमा पार नशा तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 28.12 किलो हेरोइन सहित चार गिरफ्तार

चंडीगढ़/फिरोजपुर, 24 मई: पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) फिरोजपुर टीम ने सीमा पार से संचालित नशा तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 28.12 किलोग्राम हेरोइन, 9.5 लाख रुपये की ड्रग मनी और एक हुंडई क्रेटा कार बरामद की है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे और उन्हें भारत में हेरोइन की खेप प्राप्त कर आगे सप्लाई करने का काम सौंपा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर गुरु हर सहाय क्षेत्र में कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

एआईजी गुरसेवक सिंह ने बताया कि आरोपियों को खेप पहुंचाने के बदले मोटी रकम देने का वादा किया गया था। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना एसएसओसी फाजिल्का में केस दर्ज कर आगे जांच जारी है।

धान सीजन में किसानों को मिलेगी निर्बाध 8 घंटे बिजली: तरुनप्रीत सिंह सौंद

चंडीगढ़, 24 मई 2026: पंजाब के बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार आगामी धान सीजन के दौरान किसानों को प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि पीएसपीसीएल ने सभी जिलों के लिए चरणबद्ध शेड्यूल जारी कर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

मंत्री ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइनें, ट्रांसफार्मर और बिजली ढांचे का रखरखाव पहले ही पूरा किया जा चुका है। राज्यभर में 24 घंटे निगरानी और खराबी के तुरंत समाधान के लिए समर्पित टीमें तैनात की गई हैं। किसानों की शिकायतों के त्वरित निपटारे हेतु कंट्रोल रूम और शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किया गया है। उन्होंने किसानों से बिजली का समझदारी से उपयोग करने और जारी शेड्यूल का पालन करने की अपील की।

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 2026-27 में 5 लाख एकड़ में होगी धान की सीधी बुवाई

चंडीगढ़, 24 मई 2026: पंजाब सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए 26 मई 2026, मंगलवार को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें और चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह अवकाश पंजाब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू रहेगा। इसके साथ ही चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के दफ्तरों और संस्थानों में भी छुट्टी रहेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को मतदान के लिए पर्याप्त समय और सुविधा मिल सके।

पंजाब में 26 मई को नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है। चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और अधिकतम मतदान प्रतिशत के साथ संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।

सरकार ने मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव शहरों और कस्बों के विकास से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए नागरिकों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक अवकाश का निर्णय केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी और लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे।

पंजाब में डीएसआर तकनीक को बढ़ावा, 2026-27 में 5 लाख एकड़ का लक्ष्य तय

चंडीगढ़, 24 मई: पंजाब में भूजल संरक्षण और धान की टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस (डीएसआर) तकनीक के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के खरीफ सीजन के दौरान 5 लाख एकड़ भूमि को डीएसआर तकनीक के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपये का विशेष बजट प्रावधान भी किया है।

कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 के खरीफ सीजन में राज्य के 23,410 किसानों ने डीएसआर तकनीक अपनाई थी, जिसके तहत 2,35,899 एकड़ क्षेत्र में सीधे धान की बुवाई की गई। किसानों को इस तकनीक को अपनाने के लिए सरकार की ओर से प्रति एकड़ 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में अब

तक 35.38 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है।

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि यह केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि जल संरक्षण की दिशा में किसानों द्वारा शुरू की गई एक बड़ी क्रांति है। उन्होंने कहा कि

वर्ष 2025-26 में किसानों से मिले सकारात्मक सहयोग ने सरकार को इस योजना का दायरा और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। अब 40 करोड़ रुपये के बजट और 5 लाख एकड़ के लक्ष्य के साथ सरकार भूजल बचाने के अपने संकल्प को और मजबूत कर रही है।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में डीएसआर तकनीक अपनाएं और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए समय रहते ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं। मंत्री ने बताया कि डीएसआर तकनीक अपनाने वाले किसानों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पहले से ही शुरू किया जा चुका है।

कृषि मंत्री ने कहा कि डीएसआर तकनीक में धान की नर्सरी तैयार करने और खेतों में पानी भरकर रोपाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे सिंचाई के पानी की खपत में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी आती है।

Advertisement

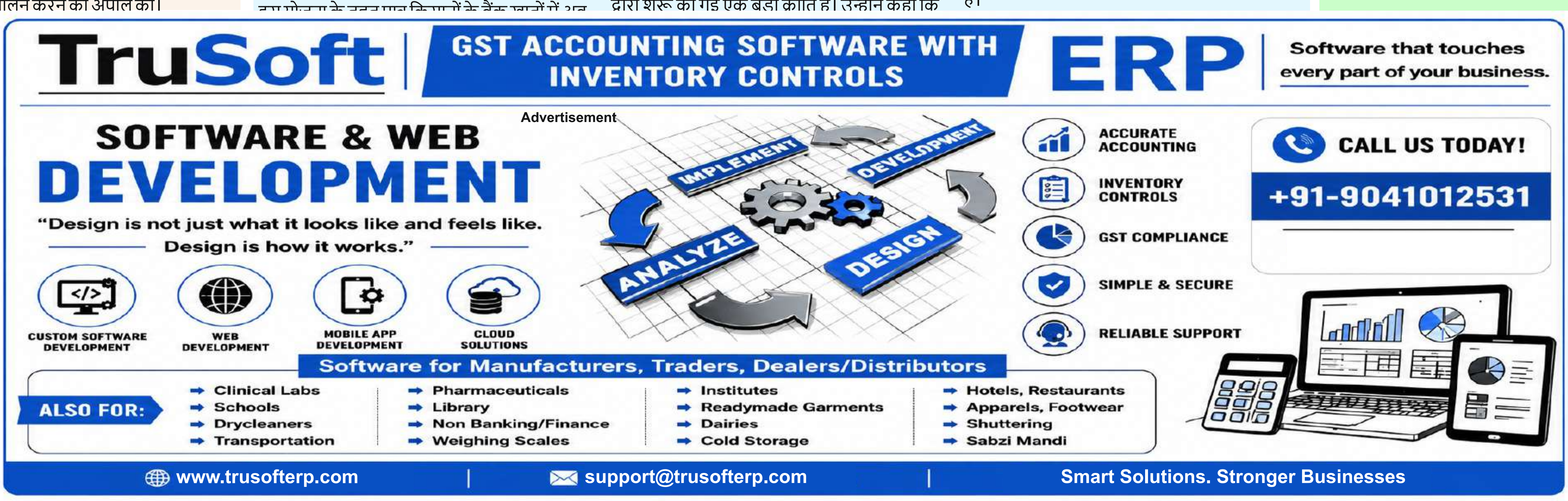

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.

PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015